

राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 पर 21 अक्टूबर से होगा तीन दिवस का कुलपति संवाद  
**राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राज्य में चरणबद्ध तरीके से होगा क्रियान्वयन—राज्यपाल**

राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा टास्क फोर्स की दूसरी विशेष बैठक

जयपुर, 06 अक्टूबर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भावनाओं और बारिकियों का समावेश परिलक्षित हो रहा है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जायेगा।

राज्यपाल श्री मिश्र मंगलवार को यहां राजभवन से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के क्रियान्वयन के लिए आयोजित टास्क फोर्स की विशेष बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च शिक्षा की चुनौतियों और कोविड-19 के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हेतु राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की पहल पर 10 अप्रैल, 2020 को टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स की बैठकें लगातार हो रही हैं। अब तक टास्क फोर्स की आठ बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में 30 अप्रैल और 06 अक्टूबर को विशेष बैठक और राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार की अध्यक्षता में 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 02 जून, और 20 अगस्त को टास्क फोर्स की बैठक हुई थीं।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बैठक में तीन निर्देश दिये—

1. राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐसे बिन्दुओं को सर्वप्रथम चिन्हित किया जाये, जिन्हें विश्वविद्यालयों में एक माह में आसानी से प्रारम्भ किया जा सकता है। विश्वास के साथ गहन चिंतन के अनुरूप कार्य करे ताकि विधिक बाधाओं का भी निराकरण हो सके।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिन बिन्दुओं पर वृहद योजना बनानी है, उसके लिए एक सप्ताह में उप समितियों का गठन करें और एक से दो माह में योजना का प्रारूप समितियों से प्राप्त कर लें।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जिन समितियों /परिषदों में विश्वविद्यालय स्तर पर परिवर्तन किये जाने हैं, उसके लिए कुलपतिगण समयानुसार कार्यवाही करें।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों का प्रारम्भिक रोडमैप तैयार हो गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने- अपने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन माइक्रो टास्क फोर्स से करा लिया है। श्री मिश्र ने कहा कि मंगलवार को टास्क फोर्स की विशेष बैठक में आये सुझावों पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से फीडबैक लिया जायेगा। इसके लिए आगामी 21 से 23 अक्टूबर तक तीन दिवसीय कुलपति संवाद होगा।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य विश्वविद्यालयों की माइक्रो टास्क फोर्स ने ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन कर राजभवन को अनुशासन भेज दी हैं। श्री मिश्र ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने की तैयारी पर प्रशंसा व्यक्त की।

श्री मिश्र ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वर्तमान में स्थापित अकादमिक व प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, नये स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू करने, एकेडमिक क्रेडिट पाइन्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार पूर्वक फार्मुलेट करने, बहुस्तरीय प्रवेश व निकास विषयों पर राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में एकरूपता एवं आम सहमति बनाने और केन्द्र सरकार से डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए सुझाव दिये हैं। राज्यपाल ने कहा कि सभी सुझावों पर कुलपति संवाद में गहन विचार- विमर्श किया जायेगा।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा स्कीम में बदलाव के साथ ही बहुविषयक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। श्री मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता व कुछ समस्याओं के निराकरण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को लागू करने के लिए विश्वास जताया है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि सकारात्मक सोच व समन्वित तरीके से समग्रता के साथ योजना को राज्य में लागू किया जा सकता है। कुलाधिपति श्री मिश्र ने कुलपतियों से कहा है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारिकियों एवं भावनाओं को समझे। राज्य में उपलब्ध परिदृश्य एवं संसाधनों को ध्यान रखे और समन्वित रूप से राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ऐसे सुझाव दें, जिससे राजस्थान नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा सके।

बैठक में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा के कुलपति प्रो. आर. ए. गुप्ता, भरतपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर.के. एस धाकरे, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉ. जे.एस. संधू, जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी. सी. त्रिवेदी, विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देवस्वरूप, पूर्व कुलपति प्रो. ए. के. गहलोत और कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री संदेश नायक ने भी विचार व्यक्त किये। प्रारम्भ में बैठक की जानकारी राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार ने दी। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविन्द राम जायसवाल भी मौजूद थे।